

>

Title : Regarding payment of arrears for mustard procured from farmers in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञापन देकर प्रचार-प्रसार करके किसानों को कम पानी की फसलें उत्पादन करने हेतु हमेशा आह्वान किया जाता रहा है। सरकारों के आह्वान को राजस्थान के किसानों ने मानकर कम पानी की फसल, सरसों की पैदावार पिछले 3 साल में खूब बढ़ाई। वर्तमान रबी की फसल में राजस्थान में सरसों का उत्पादन 40 लाख मैट्रिक टन के आस-पास हुआ। केन्द्र सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 1715 रुपये घोषित किया और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन नेफेड द्वारा राजस्थान की एजेंसी राजफेड से खरीद करवाई। राजस्थान में इस रबी बम्पर फसल होने के फलस्वरूप राज्य सरकार की एजेंसी राजफेड ने 14.18 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद की और केन्द्र सरकार की एजेंसी ने नेफेड को 13.45 लाख मैट्रिक टन का ही भुगतान करने की स्वीकृति दी। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने पहले कहा था कि 14 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद पर सहमति व्यक्त की थी। खरीदी हुई सरसों का भुगतान भी 3-4 महीने में होता है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश में इस रबी की गई सरसों की खरीद 14.18 लाख मैट्रिक टन के पेटे 137.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि, जिसकी सहमति सरकार ने दी है, उसका भुगतान शीघ्र किया जाए ताकि किसानों को उनका पूरा भुगतान किया जा सके। राज्य सरकार ने केन्द्र के पूरे आश्वासन पर अपनी ओर से किसानों का भुगतान किया था।...(व्यवधान) राजस्थान के सारे जिलों में यह समस्या है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय :

श्री सुभा महारिया को भी उनके साथ एसोसिएट कर दिया जाए।